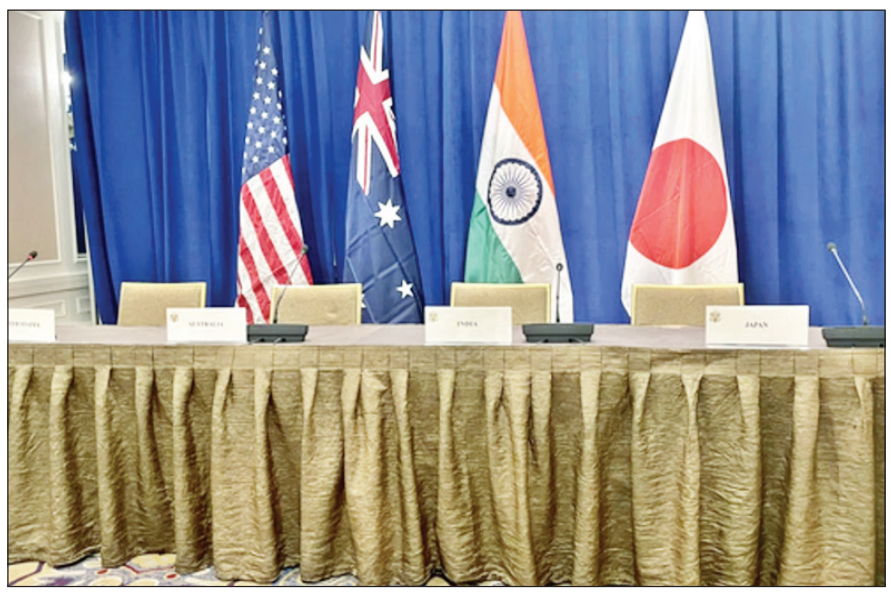
नईदुनिया



क्वाड शिखर सम्मेलन : भारत वाली चौकड़ी ने चीन को दिया झटका

मनीला

करीब दो सालों के अंतराल के बाद हुए क्वाड शिखर सम्मेलन ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चाबंदी जारी रहने का स्पष्ट संदेश दिया है। इस बैठक ने अमेरिका और चीन के बीच समीकरण बदलने की अटकलों पर भी विराम लगाया है।

मनीला में यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब चीन और मेजबान फिलीपींस के बीच तनातनी अपने चरम पर है। यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति के चीन दौरे के ठीक एक दिन पहले हुआ, जहां वे चीनी राष्ट्रपति और रूसी समकक्ष के साथ बैठक करेंगे। इस तरह अमेरिका ने भी चीन को स्पष्ट संदेश दिया है कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को लेकर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।

बता दें कि क्वाड की पिछली बैठक 2024 में अमेरिका में हुई थी और 2025 के लिए इसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई थी। हालांकि, उस समय बने राजनीतिक हालातों के कारण यह बैठक नहीं हो पाई। इस दौरान कुछ हलकों में क्वाड के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रयासों से क्वाड को फिर से सक्रिय करने में सफलता मिली। बीते मई में भारत में हुए क्वाड के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के बाद मनीला में शिखर सम्मेलन के आयोजन से एक बार फिर भारत, जापान, आस्ट्रेलिया और अमेरिका इस मंच पर एकजुट हुए हैं। उन्होंने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन और स्वतंत्र नौवहन के महत्व पर सहमति जताई है। यह चीन के लिए एक कूटनीतिक झटका है और भविष्य के लिए स्पष्ट संदेश भी कि क्वाड कायम है। जानकार मनीला सम्मेलन को एक बड़ी कूटनीतिक घटना मानते हैं। इसकी एक अहम वजह यह भी है कि क्वाड की स्थापना भी 2007 में मनीला में हुई थी, जब वहां नेता आसियान शिखर सम्मेलन में जुटे थे।

मनीला में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में क्वाड देशों ने भविष्य के सहयोग के लिए चार प्रमुख पहलों की घोषणा की है। इनमें सबसे पहले 2027 में मुंबई में होने वाला पहला क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम शामिल है, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। इसका उद्देश्य चारों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। दूसरी महत्वपूर्ण पहल एआई एक्सेलेरेटर है, जिसका लक्ष्य पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तक पहुंच को आसान बनाना, इसके उपयोग को बढ़ावा देना और संबंधित प्रयासों को वित्तीय सहयोग देना है। तीसरी पहल हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी है, जो समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके तहत 2027 में पहली बार क्वाड के पी-8 और पी-3सी गश्ती विमान समुद्री सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत होगी। चौथी पहल केबल कनेक्टिविटी को मजबूती देने से जुड़ी है, जिसके तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और भरोसेमंद संचार बुनियादी ढांचे तक पहुंच का विस्तार किया जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

अमेरिका में बसना अब हुआ सपना, 10 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड मिलने का कर रहे इंतजार



वाशिंगटन। भारतवंशियों के लिए अमेरिका में बसने का सपना अब मुश्किल होता जा रहा है। ग्रीन कार्ड मिलने में सालों की देरी, ट्रम्प प्रशासन की सख्त वीजा नीतियां और नस्लीय भेदभाव की आशंका इसकी बड़ी वजह हैं। अमेरिका की नेशनल फाउंडेशन फार अमेरिकन पालिसी के मुताबिक करीब 10 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले करीब 30 हजार भारतीयों ने दूसरे देशों की स्थायी रेजिडेंसी भी हासिल कर ली है। माइग्रेशन एजेंसियों के मुताबिक ये लोग अमेरिका के साथ-साथ दूसरे देशों में भी अपना ठिकाना तैयार कर रहे हैं। इनमें दुबई और यूरोप के देश सबसे पसंदीदा विकल्प बनकर उभरे हैं। मिलियनेयर माइग्रेंट फर्म के जेरेमी सैवरी के मुताबिक भारतीय अब अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में भी बसने के विकल्प तलाश रहे हैं। ट्रम्प की सख्त वीजा नीतियां और नस्लीय भेदभाव की आशंका भी इसकी वजह हैं। दुबई का बिजनेस फ्रेंडली माहौल और गोल्डन वीजा भारतीयों को आकर्षित कर रहा है। वहीं, यूरोप में ग्रीस की रेजिडेंसी से शेंगेन क्षेत्र के देशों में यात्रा करना आसान हो जाता है। स्पेन का डिजिटल नोमैड वीजा रिमोट काम करने वालों को वहां रहने का विकल्प देता है। इटली में निवेश के जरिए पीआर हासिल करना भी संभव है। इमिग्रेशन कंसल्टिंग फर्म गारंट इन के आंद्रेई बोइको के मुताबिक भारतीय अब अमेरिका के अलावा आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड में बसने के विकल्पों के बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं। इन देशों में माइग्रेशन को लेकर पूछताछ में सालाना 50फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

अमेरिकी युवाओं में दस वर्षों में घटा शराब पीने का प्रतिशत



न्यूयार्क। अमेरिका में 18 से 29 साल के युवाओं में हर सप्ताह शराब पीने वालों का आंकड़ा पिछले दस वर्षों में 16 प्रतिशत घटा है। अमेरिका में जेन-जी के बीच शराब पीने का चलन लगातार कम हो रहा है। युवा अब सेहत और खर्च को प्राथमिकता देते हुए शराब से दूरी बना रहे हैं। गैलप के विश्लेषण के मुताबिक, वर्ष 2015-17 के दौरान इस आयु वर्ग के 71 प्रतिशत युवा हर सप्ताह शराब पीते थे। वहीं, 2024-26 में यह आंकड़ा घटकर 55 प्रतिशत रह गया। युवाओं में एक बार में अधिक मात्रा में शराब पीने की प्रवृत्ति भी कम हुई है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार, वर्ष 2025 में 19 से 30 साल के 24 प्रतिशत युवाओं ने हाल के दिनों में एक बार में पांच या उससे अधिक ड्रिंक लिए थे। करीब एक दशक पहले यह आंकड़ा 31 प्रतिशत था। सर्वे के मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में युवा दूसरे आयु वर्गों की तुलना में भी कम शराब पी रहे हैं। युवाओं के इस बदलते रुझान के पीछे कई वजहें सामने आई हैं। इनमें आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और सामाजिक व्यवहार से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिका में युवाओं के बीच शराब पीने की आदत पिछले चार दशकों से लगातार घट रही है। दूसरी ओर, भारत में तस्वीर इसके उलट दिखाई दे रही है। यहां शराब पीने वाले युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

बगैर पेड़-पौधों के भी रह सकती थी पृथ्वी पर जिंदगी के अनुकूल परिस्थितियां

वाशिंगटन। पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी के बिना भी महासागर और रहने योग्य तापमान बरकरार रह सकते थे। हालांकि, ऐसी धरती के वातावरण में आक्सीजन की भारी कमी होती। अमेरिका की यूनिवर्सिटी आफ वाशिंगटन के शोधकर्ताओं की इस स्टडी में यह दावा किया है। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने करीब 5 अरब साल के दौरान पृथ्वी के विकास का एक वैकल्पिक माडल तैयार किया। इस माडल में पेड़-पौधों, इंसानों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह हटा दिया गया, जबकि पृथ्वी की अन्य प्राकृतिक और भौतिक प्रक्रियाओं को पहले की तरह जारी रखा गया। शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि किसी ग्रह को रहने योग्य बनाए रखने के लिए जीवन की मौजूदगी वास्तव में कितनी जरूरी है। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने गैया हाइपोथिसिस को भी नए नजरिए से परखा। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर मौजूद जीव-जंतु और वनस्पतियां अपने पर्यावरण के साथ मिलकर ग्रह के तापमान और वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, नए सिमुलेशन से पता चला कि जीवन के बिना भी पृथ्वी की कई प्राकृतिक प्रक्रियाएं पर्यावरण को स्थिर बनाए रख सकती थीं। शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर माडल में पृथ्वी के कोर, मेंटल, बाहरी परत, महासागरों और वायुमंडल को शामिल किया। इसके अलावा सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, धरती के भीतर गर्मी का प्रवाह, समुद्र की रासायनिक संरचना और सतह के तापमान जैसे कुल 19 महत्वपूर्ण पैमानों का अध्ययन किया गया।

बांग्लादेश में रातभर हिंसा, सांसद का घर, थाना, रेलवे स्टेशन, वाहन फूंके, पुलिस लाकअप में बंद लोगों को छुड़ाया, कृषक दल नेता की हत्या

ढाका (बांग्लादेश)

बांग्लादेश अवामी लीग (बीएएल) की नेता और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में स्वदेश वापसी करने की घोषणा से मची राजनीतिक हलचल के बीच देश में तेजी से अराजकता फैल रही है। देश के कई हिस्सों में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। भीड़ थानों तक में आग लगाने को आमादा है। नेताओं के घरों को फूंका जा रहा है। सरकारी वाहनों को पेट्रोल छिड़ककर कर आग के हवाले किया जाने लगा है। यही नहीं हिरासत में लिए गए लोगों को पुलिस लाकअप से जबरिया छुड़ाया जा रहा है।

द डेली स्टार और ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, कई जगहों पर हिंसा हुई है। गोपालगंज में हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए हैं। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर, थाना और पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया है। हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़ा ले गए हैं। हिंसा में कृषक दल के एक नेता की जान चली गई है। तुंगीपाड़ा में रात को अशांति के बीच उपद्रवियों ने गोपालगंज-तुंगीपाड़ा सड़क पर, निलफा बाजार के पास कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। रात करीब 9:00 बजे चार गाड़ियों को जलाया गया। इनमें बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की दो गाड़ियां भी शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, गोपालगंज के तुंगीपाड़ा उपजिला में सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सांसद एसएम जिलानी के घर और स्थानीय पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। फरीदपुर के भांगा उपजिला में रात को अवामी लीग के समर्थन में निकाले गए एक जुलूस के दौरान हुई हिंसा में बीएनपी के कृषक दल के एक नेता की हत्या कर दी गई। तुंगीपाड़ा उपजिला के



प्रशासनिक अधिकारी (निर्वाही अधिकारी) मोहम्मद दीदारुल आलम ने पुष्टि की कि पटगाती बाजार इलाके में जिलानी के घर में आग लगा दी गई है। यह घटना रात 8:30 बजे से 9:00 बजे के बीच हुई। इसके अलावा इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इसमें लोगों को जय बांग्ला, जय बंगबंधु और जय हसीना के नारे लगाते देखा जा सकता है।

यह हमला तब हुआ, जब अवामी लीग और उससे जुड़े प्रतिबंधित संगठनों के कथित समर्थकों ने तुंगीपाड़ा थाने पर धावा बोल दिया। यह घटना पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद हुई। चश्मदीदों के अनुसार, मस्जिद के लाउडस्पीकर पर घोषणा होने के बाद पार्टी समर्थक थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और परिसर को घेर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारियों को अवामी लीग के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा गया। पुलिस ने साउंड ग्रेनेड, आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। इससे स्थिति और खराब हो गई। दोनों पक्षों के बीच झड़पें शुरू हो गईं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, हालात यह पैदा हो गए कि पुलिसकर्मी थाने से पीछे हट गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी और पुलिस लाकअप में बंद प्रतिबंधित छात्र लीग के समर्थकों को छुड़ा कर अपने साथ ले गए। आसपास के लोगों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने निलफा बाजार के पास गोपालगंज-तुंगीपारा सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिससे दमकल की गाड़ी थाने तक नहीं पहुंच सकी। तुंगीपारा फायर सर्विस के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण वे तुरंत पुलिस थाने नहीं पहुंच सके। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो में लोगों को जाय बांग्ला, जाय बंगबंधु और जाय हसीना के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है।

चश्मदीदों के अनुसार, कृषक दल की भांगा उपजिला इकाई के संयुक्त सचिव 34 वर्षीय राजू मोल्ला की एक देसी बम विस्फोट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, रात लगभग 9:15 बजे ढाका-बारीसाल राजमार्ग पर हमिरदी बस स्टैंड से अवामी लीग समर्थकों का एक जुलूस निकला। जुलूस में शामिल लोगों ने बीएनपी के एक कार्यालय में भी तोड़फोड़ की। इसी दौरान, राजू के पास एक देसी बम फटा। उन्हें तत्काल भांगा उपजिला स्वास्थ्य परिसर ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भांगा उपजिला बीएनपी अध्यक्ष खांडेकर इकबाल हुसैन सलीम ने आरोप लगाया कि अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने राजू को अकेला पाकर उनकी हत्या कर दी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मो. रेहान गफ़ूर ने कहा कि पुलिस अभी मौत के कारण की पुष्टि नहीं कर सकती। विपक्ष के नेता और जमात अमीर शफीकुर रहमान ने कल संसद में गोपालगंज की बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गहरी चिंता जताई। फेसबुक लाइव प्रसारण में एचएम रुबेल फराजी नाम के एक व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में आग लगाने की धमकी देते हुए सुना गया। इस फुटेज की सच्चाई और पूरी परिस्थितियों की तुरंत स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। पुलिस मुख्यालय की प्रवक्ता कमरम मुनीरा ने रात करीब 9:10 बजे पुष्टि की कि तुंगीपारा पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया और उसमें आग लगा दी गई। उन्होंने बताया कि पुलिस को वाहनों में आग लगाए जाने की भी सूचना मिली है।

इससे पहले पुलिस मुख्यालय के डीआईजी (अपराध और संचालन) मोहम्मद अबू सुफियान ने कहा कि थाने को घेर लिए जाने की सूचना मिलने के बाद अधिकारी जानकारी जुटा रहे है। तुंगीपारा फायर सर्विस के कार्यवाहक स्टेशन अधिकारी एस्कंदर शेख ने बताया कि दमकलकर्मियों को पुलिस स्टेशन, चौरांगी चौराहे और बशबारिया के पास आग लगने की सूचना मिली। हालांकि, सुरक्षा कारणों से दमकलकर्मी प्रभावित जगहों तक नहीं पहुंच सके।

बांग्लादेश : 16 दिसंबर को हसीना की घर वापसी या गृहयुद्ध की आहट

ढाका



बांग्लादेश की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहाँ इतिहास और भविष्य का टकराव स्पष्ट नजर आ रहा है। एक महीने बाद 16 दिसंबर को बांग्लादेश अपना विजय दिवस मनाएगा, जो 1971 में शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में मिली आजादी का प्रतीक है। लेकिन इस बार यह तारीख बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नींद उड़ा रही है। उम्मीद की जा रही है कि निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना किसी भी कीमत पर इसी दिन वतन वापसी करेंगी, जिसकी संभावना तारिक सरकार के लिए पराजय दिवस में बदल सकती है। यह वापसी जितनी सीधी दिखती है, बांग्लादेश की सियासत और सड़कों के लिए उतनी ही खतरनाक भी है।

फरवरी के चुनावों में सत्ता में लौटे बीएनपी नेता तारिक रहमान के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। ईरान युद्ध के चलते गहराता आर्थिक संकट, गारमेंट इंडस्ट्री में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बढ़ता असंतोष, और अब शेख हसीना की संभावित वापसी ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। उन्हें एक तरफ प्रतिबंधित अवामी लीग के मंसूबों को नाकाम करना है, जिसके कार्यकर्ता हसीना की वापसी के ऐलान से उत्साहित हैं। दूसरी तरफ, जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियों की चुनौती है, जो अवामी लीग के नाम पर हिंसक टकराव के लिए तैयार रहती हैं। शेख हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग से नया पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मांगा है, जिसे एक सोची-समझी राजनीतिक चाल माना जा रहा है। यह कदम उन्हें ढाका में अनुकूल माहौल होने पर वापसी करने या प्रतिकूल परिस्थितियों में पासपोर्ट न मिलने को बहाना बनाकर यात्रा टालने की सुविधा देता है। इस तरह उन्होंने राजनीतिक खेल को पूरी तरह खुला रखा है।

जमीन पर भी तनाव साफ दिख रहा है। अवामी लीग का गढ़ माने जाने वाले गोपालगंज जिले में सशस्त्र रैलियां, बीएनपी नेताओं के घरों पर तोड़फोड़, ग्रामीण बैंक शाखाओं में आगजनी और पुलिस वाहनों पर हमले की खबरें आ रही हैं। हालात इतने बेकाबू हैं कि कानून-व्यवस्था संभालने के लिए बार्डर गार्ड बांग्लादेश की टुकड़ियों को तैनात करना पड़ा है। अफसरशाही में भी दरार साफ है। चटगांव के एसपी मोहम्मद जहांगीर आलम की देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी और गोपालगंज के डीसी, एसपी समेत तीन ओसी के तबादले से पता चलता है कि प्रशासन के भीतर अवामी लीग के प्रति सहानुभूति रखने वालों की कमी नहीं है। गिरफ्तार एसपी के संदेश दिसंबर करो या मरो का जुआ है, लोग मधुमक्खियों के झुंड की तरह सड़कों पर उतरेंगे ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ढाका सरकार कागजों पर भले ही हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती रही हो (उन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है), लेकिन अंदरूनी तौर पर तारिक रहमान सरकार उनके बांग्लादेशी जेल में होने से सबसे ज्यादा घबरा रही है।

प्रिंस विलियम और केट ने पीएम मोदी से की मुलाकात

व्यापार-रक्षा और तकनीक पर चर्चा



नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी प्रिंसेस केट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारत-ब्रिटेन के बीच व्यापार, रक्षा और तकनीक सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों की पीएम मोदी से पिछली मुलाकात अप्रैल 2016 में हुई थी। बुधवार को प्रिंस विलियम ने मुंबई में करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस कार्यालय का दौरा किया। यहां करीना कपूर, सैफ अली खान और करण जौहर ने उनका स्वागत किया। भारतीय और ब्रिटिश फिल्म उद्योग के बीच सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। वहीं, प्रिंसेस केट ने नौरोजी वाडिया मैटरनिटी अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने मां और नवजात बच्चों की देखभाल से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी ली।

लाहौर में पुलिस ने पीटीआई के तीन नेताओं को हाई कोर्ट से बाहर निकलते ही गिरफ्तार किया

इस्लामाबाद (पाकिस्तान)

कई साल से रावलपिंडी की जेल में बंद अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता तैमूर सलीम झागरा, कामरान बंगश और इरफान सलीम को पेशावर उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई को हुए हमले के सिलसिले में की गई है।



द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तारी के समय हाई कोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस अधीक्षक (आपरेशंस) फरहान खान अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। पुलिस ने बताया कि तीनों नेता रेडियो पाकिस्तान हमले के मामले में आतंकवादरोधी अदालत के जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद अंतरिम जमानत की मांग करने हाई कोर्ट पहुंचे थे। हिरासत में लिए जाने से पहले वे हाई कोर्ट के बार रूम में मौजूद थे। हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की याचिकाओं को मंजूर कर लिया था।

गौरतलब है कि रेडियो पाकिस्तान हमले के मामले में आतंकवादरोधी अदालत द्वारा मांगी गई पंजाब फारेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट में 9 मई 2023 की घटनाओं से जुड़े फुटेज में सलीम सहित कई पीटीआई नेताओं की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी। लैब ने पेशावर पुलिस के अनुरोध पर एक यूएसबी डिवाइस में दी गई 16 वीडियो क्लिप की जांच की। विश्लेषण में इन नेताओं की प्रोफाइल तस्वीरों और फुटेज में दिख रहे व्यक्तियों के बीच समानताएं पाई गईं। रिपोर्ट में दो वीडियो क्लिप में छेड़छाड़ के सबूत भी मिले हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के अलावा इरफान सलीम से जुड़े हैं। यह फारेंसिक जांच 19 से 23 दिसंबर 2025 के बीच की गई। बताया गया है कि 9 मई को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो के वारंट के तहत इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस ऐतिहासिक इमारत पर हमला कर दिया। खान की गिरफ्तारी से पार्टी कार्यकर्ता भड़क गए और देश के कई शहरों में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें सैन्य प्रतिष्ठान भी शामिल थे। पेशावर भी उन शहरों में से एक है जहां तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने रेडियो पाकिस्तान की ऐतिहासिक इमारत पर धावा बोला। जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद उन्होंने इमारत में आग लगा दी। इस भीषण आग में कई महत्वपूर्ण रिकार्ड और अन्य बेशकीमती चीजें जलकर राख हो गईं।

बालेन्द्र शाह के भारत दौरे में उठेगा चीनी ठेकेदारों के जलविद्युत प्रोजेक्टों से बिजली खरीद का मुद्दा, अपर तामाकोशी को मंजूरी दिलाने की मांग करेगा नेपाल

काठमांडू

नेपाल लंबे समय से इस बात की मांग करता रहा है कि भारत न केवल चीनी निवेश वाले, बल्कि चीनी ठेकेदारों द्वारा बनाए गए जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली खरीदने की अनुमति नहीं दे। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के भारत दौरे के दौरान नेपाल इस मांग को भारत के सामने रखेगा। साथ ही, 456 मेगावाट क्षमता वाली अपर तामाकोशी परियोजना सहित चीनी ठेकेदारों की भागीदारी में निर्मित अन्य जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली निर्यात की अनुमति देने की मांग करेगा।

नेपाल लंबे समय से भारत को बिजली निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, 456 मेगावाट की अपर तामाकोशी सहित चीनी ठेकेदारों के माध्यम से निर्मित कई परियोजनाओं को अब तक भारतीय बाजार में बिजली बेचने की अनुमति नहीं मिल सकी है। परियोजनाओं में चीनी ठेकेदारों की भागीदारी को भारत ने मंजूरी प्रक्रिया में बाधा के रूप में लिया है।

अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजना में चीनी कंपनी सिनो हाइड्रो ने सिविल निर्माण का काम किया था। हालांकि, परियोजना के हाइड्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े कार्य भारतीय कंपनियों ने किए थे। इसके बावजूद चीनी कंपनी की भागीदारी के कारण भारत ने इस परियोजना से बिजली निर्यात को मंजूरी नहीं दी है।

भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2021 में सीमा पार बिजली आयात-निर्यात से संबंधित कार्यविधि जारी की थी। इसके तहत भारतीय बाजार में बिजली बेचने के लिए प्रत्येक जलविद्युत परियोजना को अलग-अलग मंजूरी लेनी पड़ती है। इस कार्यविधि में प्रावधान है कि भारत के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग समझौता नहीं करने वाले पड़ोसी तीसरे देशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश अथवा नियंत्रण रखने वाली कंपनियों की परियोजनाओं से भारत बिजली नहीं



खरीदेगा। वर्ष 2018 में जारी सीमा पार बिजली व्यापार संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार इस कार्यविधि की धारा 6.3 में ऐसा प्रावधान है। हालांकि, इसमें सीधे तौर पर यह नहीं कहा गया है कि चीनी निवेश वाली सभी परियोजनाओं से बिजली नहीं खरीदी जाएगी। लेकिन चीन और भारत के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौता नहीं होने के कारण नेपाल में चीनी निवेश या नियंत्रण वाली परियोजनाओं से उत्पादित बिजली को भारतीय बाजार में बेचने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। हालांकि, इस कार्यविधि में चीनी ठेकेदारों द्वारा निर्माण किए गए प्रोजेक्टों से बिजली खरीदने पर स्पष्ट रोक नहीं है। इसके बावजूद भारत के नियामक निकाय ने अब तक चीनी ठेकेदारों की भागीदारी वाली किसी भी जलविद्युत परियोजना से बिजली खरीदने की अनुमति नहीं दी है। नेपाल का तर्क है कि किसी परियोजना में चीनी कंपनी का केवल ठेकेदार होना और उसका निवेशक होना दो अलग-अलग बातें हैं। इसलिए ठेकेदारी में चीनी कंपनियों की भागीदारी के आधार पर नेपाली बिजली के निर्यात को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। नेपाल इससे पहले भी अपर तामाकोशी के अलावा अपर भोटेकोशी, मर्स्यांगदी, कालीगंडकी-ए और मध्य मर्स्यांगदी जैसी जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली को भारतीय बाजार में बेचने की अनुमति मांग चुका है। हालांकि, इन परियोजनाओं में अपर तामाकोशी से बिजली निर्यात की मंजूरी का मामला अब तक लंबित है।